



महिला सशक्तिकरण में वूमन 20 की भूमिका: एक विश्लेषण

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र

राजकीय महिला महाविद्यालय, ढिरुई, पट्टी, प्रतापगढ़

सारांश : G20 ने दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप को स्थापित किया है, वूमन 20 ने विश्व स्तर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक नागरिक जुड़ाव समूह के तौर पर शुरू किए गए महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा अब G20 के एजेंडे के केंद्र में है। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित समाजवैज्ञानिक विश्लेषण हैं।

मुख्य शब्द : वूमन 20, आर्थिक सुरक्षा, वूमेन लीडर्स, जेंडर, शक्ति

कोरोना महामारी की दुनिया में दस्तक से पहले, सुरक्षित आजीविका तक अपनी पहुंच बनाने के लिए महिलाओं को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। साल 2014 में घोषित ब्रिस्बेन '25x25' लक्ष्यों ने 2025 में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की है और यह महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित जी 20 नेताओं की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक बताया जा रहा है। एक ऐसी दुनिया जो वापस पटरी पर आने की कोशिश कर रही है, जहां अभी भी महामारी का दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसने दुनिया भर में महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित किया है। अतिरिक्त देखभाल की ज़िम्मेदारियां, घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी, रोज़गार के अवसरों में कमी और सरकारी सहायता तक कम पहुंच का मतलब यह है कि कोरोना महामारी का प्रभाव महिलाओं के जीवन में मौजूदा नुकसान को और बढ़ा सकता है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को आगे बढ़ाने में बहुपक्षवाद और जी 20 की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है। दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने की तात्कालिकता स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है क्योंकि बहुपक्षीय व्यवस्था मौजूदा वक्त में दबाव में है। G 20 और दूसरों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह वास्तविक प्रभाव के साथ क्या हासिल कर सकता है – महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा इन मुद्दों में से प्रमुख है। (1,2)

यह विदित हैं की 25×25 लक्ष्य के लिए G20 की प्रतिबद्धता के बाद वूमन 20 की स्थापना 2015 में तुर्की के राष्ट्रपति पद के दौरान की गई थी। आधिकारिक इंगेजमेंट ग्रुप की मौजूदा स्थिति के साथ, वूमन 20 का उद्देश्य उद्यमियों, व्यापारिक लोगों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और अन्य लोगों को महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर G20 को सिफारिशें बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। G20 देशों को पता है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से घरेलू और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, यह आश्वर्यजनक नहीं है कि तुर्की के बाद वूमन 20 ने अक्सर उच्च स्तर की पहुंच का लाभ उठाया। साल 2018 में राष्ट्रपति मौरिसियो मैक्री ने मंच पर वूमन 20 की नीतिगत सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जैसा कि जापान में 2019 में प्रधानमंत्री शिंज़ो अबे ने किया था। इसके साथ ही सऊदी अरब की सरकार ने महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जिसने प्रशासनिक रूप से प्रभावी डब्ल्यू 20 कार्यालय को और सक्षम बनाया और यह कोरोना महामारी के पहले साल के दौरान विशेष रूप से अहम था। डब्ल्यू 20 प्रक्रियाएं एक समय में, आम तौर पर में राउंडटेबल शेड्यूल शामिल होते हैं, जो पूरे वर्ष निर्धारित रहते हैं और मेज़बान देश में एक अंतिम शिखर सम्मेलन के तौर पर इसकी समाप्ति होती है। गोलमेज सम्मेलन अक्सर यूरोप या अमेरिका में आयोजित किए जाते थे और अन्य प्रमुख जेंडर केंद्रित घटनाओं के साथ मेल खाते थे। कम प्रक्रिया वाले इस प्रोग्रामिंग के वार्षिक कैलेंडर में फेरबदल किया गया है, जिसमें शुरूआती और समापन कार्यक्रम, विषयगत-संबंधित सम्मेलन, विभिन्न कार्यबल और कार्य समूह के बारे में जानकारी शामिल है। कोरोना महामारी के अलग-अलग अनुभवों को देखते हुए इन आयोजनों को ऑनलाइन, कभी व्यक्तिगत रूप से और कभी-कभी हाइब्रिड डिलीवरी के माध्यम से आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन लिंग पर केंद्रित जी 20 तंत्र के भीतर अन्य आंदोलनों के साथ-साथ इसका मतलब है कि वूमन 20 अक्सर अपने मक्सद को खो देता है और मुख्य आयोजन से अलग एक कार्यक्रम भर रह जाता है। (1,3,4)

साल 2018 में बिज़नेस वूमेन लीडर्स टास्कफ़ोर्स की स्थापना “महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने के लिए कार्रवाई योग्य, मापने योग्य और परिणाम-संचालित समाधानों” पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी। सरकार के प्रमुखों ने अपने देश के प्रतिनिधि को नियुक्त किया और जी 20 में जेंडर के लिए एक आधिकारिक, फिर भी गैर-सरकारी आवाज़ बन कर उभरा। बीडब्ल्यूएल कार्यबल के पास वूमन 20 के समर्थन के लिए कोई आधिकारिक रास्ता नहीं बचा था लेकिन अक्सर इसके सदस्य वूमन 20 प्रतिनिधि ही हुआ करते थे। कुछ के लिए इसने संचार के लिए एक रास्ता खोल दिया। साल 2020 में बीडब्ल्यूएल टास्कफ़ोर्स को समाप्त कर दिया गया और एक नई पहल, वूमन 20 एलायंस फ़ॉर द एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ़ वूमेन इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन (जी 20 एम्पॉवर), कनाडा के नेतृत्व में एक पहल के साथ बदल दिया गया। एम्पॉवर का उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र से सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के साथ महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को आगे बढ़ाना भी है। कुछ मामलों में एम्पावर की स्थापना ने एक शक्ति संरचना को आगे बढ़ाया जहां इसे वूमन 20 के सरकारी ट्रैक से समर्थन प्राप्त हुआ। एम्पॉवर के ट्रिटर अकाउंट में कहा गया है कि यह महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेज़ी लाने के लिए व्यवसायों और सरकारों के बीच सबसे अधिक समावेशी और कार्रवाई आधारित गठबंधन है। जी 20 के भीतर दो तंत्रों के बीच एक शक्ति संघर्ष भी जारी है और डब्ल्यू 20 के लिये यह चिंता का विषय है कि यह तेज़ी से अप्रासंगिक होता जा रहा है। जी 20 तंत्र में जेंडर अब पहले से कहीं अधिक अंतर्निहित हो चुका है। (1,2,3)

विश्लेषकों की राय हैं की वूमन 20 में कुछ सुधार की आवश्यकता है। भारत 2023 में ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है क्योंकि तब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जी 20 ट्रैइका के सबसे नए सदस्य के रूप में भारत को निश्चित रूप से वर्तमान अध्यक्ष, इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह जानने और समझने के लिए कि जी 20 कूटनीतिक कार्य कैसे पूरा करता है। ऐसा करने में भारत यह समझने के लिए अतीत

की ओर देख सकता है कि वह अपने संसाधनों का सबसे बेहतर आवंटन कैसे कर सकता है और वुमन 20 के असर को और व्यापक बना सकता है। इसके आधार पर वुमन 20 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भारत तीन चीज़ें कर सकता है - उम्मीद करना, सुधार करना और स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करना। भारत को वुमन 20 से यही अनुमान लगाना चाहिए और सीखने के बजाय विशेषज्ञता की स्थिति से शुरुआत करनी चाहिए। घटनाओं के एक साल के कैलेंडर को शामिल करने के लिए वुमन 20 एजेंडे का विस्तार अक्सर स्वास्थ्य या उद्यमिता जैसे विषय पर केंद्रित होता है। ऐसा लगता है कि वुमन 20 की विशेषज्ञता पाने के बजाय, ये आयोजन कूटनीति के लिए एक मंच और विषयों पर प्रतिनिधियों को शिक्षित करने की प्रक्रिया बन गई है। यह एक बड़ी समस्या है कि वुमन 20 बड़े पैमाने पर सीमित संसाधनों वाले स्वयंसेवकों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बन गया है। इसके साथ ही वे अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी और अर्थशास्त्री सहित विश्व-अग्रणी विशेषज्ञ भी होते हैं। इसका मतलब है कि वुमन 20 में जाने के लिए विशेषज्ञता की शर्त पहले से ही है। उन्हें आमतौर पर जेंडर आधारित मुद्दों में नवीनतम विकास के बारे में सीखने के दिनों की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वे उस ज्ञान के साथ पहले से ही आगे रहते हैं। जबकि भारत के लिए विशेषज्ञता की मौजूदा शर्त है, नए और महत्वपूर्ण अपडेट और विकास के लिए ज्ञान भागीदारों के साथ काम करना। इस पर वुमन 20 के शुरुआती महीनों में काम किया जा सकता है और एक संक्षिप्त ब्रीफिंग के रूप में प्रतिनिधियों को बताया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कम घटनाएँ और वास्तव में गंभीर रूप से, पहले से ही संसाधन की कमी वाले प्रतिनिधियों के लिए कम धन की आवश्यकता होगी। वुमन 20 के सात वर्षों के बाद अब मुद्दों की पहचान हो रही है और कोशिश यही होनी चाहिए कि जी 20 के दौरान ध्यान समाधान की ओर होना चाहिए। वुमन 20 की प्रक्रिया में सुधार इसकी शक्ति के तौर पर सामने आना चाहिए। इस प्रक्रिया सुधार के दो घटक हैं जिन्हें भारत 2023 में आगे बढ़ा सकता है। पहला, वुमन 20 को जेंडर पर विशेषज्ञता के साथ जी 20 के संसाधन के रूप में देखे जाने की ज़रूरत है। जी 20 द्वारा जारी किए गए हर आधिकारिक बयान के साथ, डब्ल्यू 20 के एक प्रतिनिधि द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए कि किसी भी नीति की सिफारिशों महिलाओं को कैसे प्रभावित करेगी। यह वुमन 20 सचिवालय को शेरपा में और वित्त बैठकों में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान कर सकता है, या कम समय के लिए परामर्श प्रक्रिया के ज़रिए इसे पूरा किया जा सकता है। वुमन 20 को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए जो जी 20 को अपनी नीतिगत सिफारिशों के साथ मदद कर सकता है। ऐसे समूह के लिए जहां सरकार की मुखिया एक महिला नहीं है। इसके अलावा दूसरा, वुमन 20 का ध्यान अपनी विज्ञप्ति और नीतिगत अनुशंसाओं पर होना चाहिए जिन्हें वुमन 20 के प्रत्याशित होने पर पहले की शर्तों के साथ विकसित किया जा सकता है। (1,5,6)

भारत को W20 को G20 प्रणाली के भीतर ऊंचा करना चाहिए। W20 को उच्च स्तरीय मंत्रियों और सरकार के प्रमुखों तक पहुंच के युग में लौटने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि W20 (और अन्य आधिकारिक जुड़ाव समूह) को G20 नेताओं को नीतिगत सिफारिशों देने के लिए एक औपचारिक मार्ग प्रदान किया जाता है। भारत का नेतृत्व, W20 को G20 में एक परामर्शी तंत्र की ओर फिर से ले जाने के लिए, इस उन्नत प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। यह G20 समुदाय को नीति निर्माण में W20 योगदान की क्षमता और महत्व पर प्रकाश डालता है। भारत W20 के लिए मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ आधिकारिक प्रतिनिधि और संचार के माध्यम से भी ऐसा कर सकता है। इन रास्तों को रेखांकित करना और भारत के प्रेसिडेंट बनने के समय से यह स्पष्ट करना एक ऐसा तरीक़ा है जो W20 को इसके ऊंचे दर्जे का संकेत दे सकता है। (1,7)

निष्कर्ष : महिलाओं के लिए आजीवन नतीज़ों में आई गिरावट की पृष्ठभूमि में जी 20 में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। वुमन 20 और अन्य समूहों जैसे कि बीडब्ल्यूएल टास्कफ़ोर्स और एम्पॉवर ने नीतिगत सिफारिशों की वक़ालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इसके बावजूद इस पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है कि वुमन 20 एक संगठन के तौर पर कहां जा रहा है और इसे लेकर जी 20 को क्या पेशकश करनी चाहिए। यह

'लैंगिक एजेंडे' के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि यह है कि कैसे उस एजेंडे की वक़ालत की जाती है और जो तेज़ी से जटिल बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देता है और जो दबाव में है। वुमन 20 को एक विशेषज्ञ समूह के लिए फिर से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो जी 20 के आधिकारिक ट्रैक को सूचित और सलाह दे सके। वुमन 20 के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है।

संदर्भ :

- 1 वॉट्सन लीन ,ई 2022: 2023 में W20 को लेकर भारत की योजना; 'पूर्वानुमान, सुधार और बुलंदी की ओर बढ़ने' में ही निहित है! ओआरएफ
- 2 Brisbane, Australia, November 2014 ,
- 3 Clare Wenham et al., "Women are most affected by pandemics — lessons from past outbreaks," Nature (blog), 8 July
- 4 NO Woman left behind, W20 Saudi Arabia 2020 Women.
- 5 Erin Watson-Lynn, "Saudi Arabia Is Not Offside on Gender Equality," The Interpreter, March 6,
- 6 G20 EMPOWER To Improve Women's Economic Empowerment and Representation in Canada and Around the World, Cision, 2021.
- 7 G20 Empower (@g20empower), Twitter

